vinetur

जर्मन मसौदा कानून में Coke Zero को प्रस्तावित शुगर टैक्स से छूट

प्रति 100 मिलीलीटर में कम से कम 5 ग्राम चीनी वाले पेयों पर €0.26 से शुरू होने वाला स्तरीय कर लगेगा।

बुधवार, 30 सितंबर 2026



जर्मनी की संघीय सरकार के विचाराधीन एक मसौदा कानून में Coke Zero जैसी चीनी-रहित पेय पदार्थों और कई अल्कोहल-रहित पेय श्रेणियों को प्रस्तावित शर्करा-युक्त पेय कर से छूट दी जाएगी, जिससे उस प्रस्ताव का दायरा सीमित हो जाएगा जिसने पहले ही राजनीतिक बहस छेड़ दी है।

t-online के अनुसार, Handelsblatt द्वारा देखे गए एक मसौदा विधेयक का हवाला देते हुए, प्रस्तावित शुगर-ड्रिंक्स टैक्स उन पेयों पर लागू होगा जिनमें प्रति 100 मिलीलीटर कम से कम 5 ग्राम चीनी हो। प्रभावित उत्पादों में सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्लेवरयुक्त या मीठे पानी, कॉन्सन्ट्रेट और सिरप शामिल होंगे। फलों और सब्जियों के जूस पर भी कर लगाया जा सकता है, हालांकि बिना अतिरिक्त चीनी वाले पेय इससे बाहर होंगे।

मसौदा आहार पूरकों और जर्मनी के दवा-कानून के तहत आने वाले उत्पादों को भी बाहर रखेगा। यह अल्कोहल-रहित वाइन, अल्कोहल-रहित स्पार्कलिंग वाइन और अल्कोहल-रहित बीयर के साथ-साथ Coke Zero जैसी चीनी-रहित सॉफ्ट ड्रिंक्स को भी बाहर रखेगा।

यह उपाय किसी पेय की कुल चीनी मात्रा के आधार पर एक स्तरीय उत्पाद शुल्क बनाएगा। Handelsblatt द्वारा वर्णित मसौदे के तहत, जिन पेयों में प्रति 100 मिलीलीटर कम से कम 5 ग्राम लेकिन 7 ग्राम से कम चीनी होगी, उन पर €0.26 की दर लगेगी। 7 ग्राम से 10 ग्राम से कम वाले पेयों पर €0.32 वसूले जाएंगे, और 10 ग्राम या उससे अधिक वाले उत्पादों पर €0.38 का शुल्क लगेगा।

जर्मन मीडिया ने बताया कि सरकार को उम्मीद है कि यह कर अगले साल €795 million जुटाएगा। 2028 से आगे, अतिरिक्त वार्षिक राजस्व लगभग €1.2 billion रहने का अनुमान है।

सरकार इस धन का उपयोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य कोष के लिए संघीय सब्सिडी में होने वाली छोटी कटौती की भरपाई में मदद के लिए करने की योजना बना रही है। यह प्रस्ताव स्वास्थ्य नीति के एक लक्ष्य को भी पूरा करता है, क्योंकि इसका उद्देश्य चीनी खपत को कम करना है।

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के वित्त मंत्री Lars Klingbeil ने इस लेवी को निष्पक्षता का मुद्दा बताया है, और तर्क दिया है कि यदि अत्यधिक चीनी सेवन से स्वास्थ्य देखभाल लागत बढ़ती है, तो उपभोक्ताओं को उस वित्तीय बोझ का अधिक हिस्सा उठाना चाहिए।

मसौदा अभी भी राजनीतिक रूप से विवादास्पद है। रूढ़िवादी Union bloc के कुछ हिस्से इस कर का विरोध कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय के पहले के प्रस्तावों में शून्य-चीनी पेयों पर कर लगाने की संभावना भी उठाई गई थी, जिसे उन उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक पदार्थों से संभावित पर्यावरणीय प्रभावों की चिंताओं से जोड़ा गया था। सार्वजनिक आलोचना के बाद Klingbeil ने इस विचार को तुरंत खारिज कर दिया, और मौजूदा मसौदा उसी बदलाव को दर्शाता दिखता है।

ये छूटें जर्मनी के पेय उद्योग में व्यापक प्रभाव डाल सकती हैं। सॉफ्ट ड्रिंक निर्माताओं के लिए, ये सीमा-मान उत्पादों को दोबारा फॉर्म्युलेट करने या उच्च कर स्लैब से नीचे रहने के लिए मूल्य समायोजित करने का दबाव बढ़ा सकते हैं। ब्रुअर्स और अल्कोहल-रहित वाइन तथा स्पार्कलिंग पेय के उत्पादकों के लिए, शून्य-अल्कोहल श्रेणियों को बाहर रखने का फैसला नई लागत बढ़ोतरी से बचने में मदद कर सकता है, ऐसे खंड में जो बढ़ रहा है और अन्यथा कीमतों में बदलाव तथा मांग में उतार-चढ़ाव का सामना कर सकता था।

मसौदा फिलहाल अंतर-मंत्रालयी समन्वय में है, यानी इसकी सरकार के भीतर अभी समीक्षा हो रही है और अंतिम मंजूरी से पहले इसमें बदलाव हो सकता है। फिर भी, इसका नवीनतम संस्करण अब तक का सबसे स्पष्ट संकेत देता है कि बर्लिन कर को कैसे परिभाषित करना चाहता है और किन पेयों को उसके दायरे में लाना चाहता है।